



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2001/अग्रहायण 23, 1923

No. 339]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2001/AGRAHAYANA 23, 1923

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकारण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2001

फा. सं. 311-4/2001-टी आर ए आई(इकॉन).—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकारण, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करने और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त अपने—अपने राजस्व की भागीदारी के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था विनियमित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकारण अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथारांशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकारण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) की उपधारा (ख) के उपर्युक्त (ख) के खंड (ii), (iii) तथा (iv) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

दूरसंचार अंतःसंयोजन (प्रभार एवं राजस्व भागीदारी) विनियम, 2001

(2001 का 5वां)

खंड I

नाम, विस्तार और प्रारंभ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

- (i) इस विनियम का नाम “दूरसंचार अंतःसंयोजन (प्रभार एवं राजस्व भागीदारी) विनियम 2001” होगा।

- (ii) इस विनियम में सेवा प्रदाताओं के बीच समूचे भारतीय क्षेत्र में तथा भारत से शुरू होकर विदेश में समाप्त होने वाली सभी दूरसंचार सेवाओं, जिनमें सीमित गतिशीलता से युक्त स्थानीय लूप में बेतार [डबल्यू एल एल(एम)] शामिल है, के अंतःसंयोजन प्रभार एवं राजस्व भागीदारी के लिए व्यवस्थाएं शामिल होंगी ।
- (iii) यह विनियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

खंड II

परिभाषाएं

2. इस विनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (i) “अधिनियम” से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 से अभिप्रेत है ।
- (ii) “प्राधिकरण” से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है ।
- (iii) “बुनियादी दूरसंचार सेवाएं” से पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पी एस टी एन) से प्राप्त सेवाएं अभिप्रेत हैं ।
- (iv) “उच्चतम (f)” से प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर यथानिर्दिष्ट दूरसंचार सेवाओं के लिए अंतःसंयोजन प्रभार की उच्चतम सीमा (सीमाएं) अभिप्रेत हैं ।
- (v) “स्वदेशी लंबी दूरी की दूरसंचार सेवा” अथवा डीएलडी का तात्पर्य किसी एक सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क के स्थानीय क्षेत्र को भारत की प्रादेशिक सीमाओं के

भीतर दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए अपेक्षित दूरसंचार सेवाओं से है ताकि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के आर-पार वायस और नॉन वायस सिग्नल के प्रेषण की अनुमति दी जा सके ।

- (vi) “फ्लोर” का तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट दूरसंचार सेवाओं के लिए अंतःसंयोजन प्रभार की उस न्यूनतम सीमा से है जिससे नीचे ऐसे प्रभार प्रस्तुत किए जाएं ।
- (vii) “स्थगन” इस बात को इंगित करता है कि प्राधिकरण ने, फिलहाल, किसी विशेष दूरसंचार सेवा के लिए कोई अंतःसंयोजन प्रभार राजस्व भागीदारी व्यवस्था अधिसूचित नहीं की है और सेवा प्रदाता ऐसी सेवा के लिए कोई भी प्रभार निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है ।
- (viii) “अंतःसंयोजन” से वे वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवस्थाएं अभिप्रेत हैं जिनके तहत सेवा प्रदाता दूसरे सेवा प्रदाताओं के ग्राहकों, सेवाओं और नेटवर्कों से संपर्क स्थापित करने के लिए अपने उपस्कर, नेटवर्क तथा सेवाओं को जोड़ देते हैं ताकि उनके ग्राहकों का उनसे संपर्क बन जाए ।
- (ix) “अंतःसंयोजन प्रभार” से वह प्रभार अभिप्रेत है जो अंतःसंयोजन के लिए एक अंतःसंयोजन प्रदाता द्वारा अंतःसंयोजन लेने वाले से वसूल किया जाता है ।
- (x) “अंतःसंयोजन प्रदाता” से वह सेवा प्रदाता अभिप्रेत है जिसके नेटवर्क से दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अंतःसंयोजन लिया जाता है ।
- (xi) “अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता” से वह सेवा प्रदाता अभिप्रेत है जो अंतःसंयोजन प्रदाता के नेटवर्क से अंतःसंयोजन लेता है ।

- (xii) “अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की दूरसंचार सेवा” से वे दूरसंचार संवाएं अभिप्रेत हैं जो भारत के भीतर सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क के स्थानीय क्षेत्र को दूसरे देश के सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क के स्थानीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए अपेक्षित होती हैं ताकि वायस और नॉन वायस सिग्नलों के संप्रेषण की अनुमति दी जा सके।
- (xiii) “अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग” अथवा आईएसडी से सार्वजनिक नेटवर्क के जरिए सीधे डायल करके भारत के अन्त्य उपभोक्ता का दूसरे देश के अन्त्य उपभोक्ता के बीच सीधा अंतःसंयोजन अभिप्रेत है।
- (xiv) “पटटाशुदा सर्किट” से उपभोक्ताओं अथवा सेवा प्रदाताओं को पटटे (लीज) पर दी गई दूरसंचार सुविधाएं अभिप्रेत हैं जिससे उन नेटवर्क टर्मिनेशन प्वाइंटों जिन्हें प्रयोक्ता पटटाशुदा सर्किट व्यवस्था के भाग के रूप में तथा जिनमें पटटाशुदा सर्किट बैंडविड्थ के लचीले प्रयोग वाली प्रणालियां भी शामिल की जा सकती हैं, के बीच टेक्नोलॉजी पारदर्शी संचारण क्षमता प्रदान की जा सके।
- (xv) “अंतःसंयोजन प्रभार में पक्षपात न करना” का तात्पर्य यह है कि सेवा प्रदाता, अंतःसंयोजन प्रभारों के मामले में सेवा प्रदाताओं के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें पर्याप्त लागत भेद का आधार शामिल नहीं है और वह भी ऐसे लागत भेद द्वारा औचित्य सिद्ध सीमा तक ही होगा।
- (xvi) “आदेश” से दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 अभिप्रेत है।
- (xvii) “प्रारंभिक नेटवर्क” से वह नेटवर्क अभिप्रेत है जिससे एक दूरसंचार संदेश के प्रवर्तक को सीधे जोड़ दिया जाता है।
- (xviii) “प्रारंभिक/ट्रांजिट/टर्मिनेटिंग सेवा प्रदाता” से वह सेवा प्रदाता अभिप्रेत है जिसका नेटवर्क दूरसंचार संदेश को प्रारंभ करने ट्रांजिट/टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

- (xix) “विनियम” से दूरसंचार अंतःसंयोजन (प्रभार एवं राजस्व भागीदारी) विनियम, 2001 अभिप्रेत है।
- (xx) “रिपोर्ट करने संबंधी शर्त” का तात्पर्य सेवा प्रदाता की उस बाध्यता से है जिसके अनुसार उसे इस नियम तथा बाद में हुए किसी परिवर्तन के तहत दूरसंचार सेवाओं के लिए किसी नए अंतःसंयोजन प्रभार और राजस्व भागीदारी की व्यवस्था लागू करने से 45 दिन पहले प्राधिकरण को रिपोर्ट देनी होती है।
- (xxi) “अंतःसंयोजन की लागत नियत करना” से किसी इंजीनियरी कार्य की वह प्रारंभिक लागत अभिप्रेत है जिसकी प्रार्थित अंतःसंयोजन सुविधाएं प्रदान करने के लिए जरूरत होती है।
- (xxii) “उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग” अथवा एसटीडी का तात्पर्य है सार्वजनिक नेटवर्क के जरिए सीधी डायलिंग करके भारत के भीतर दो उपभोक्ताओं के बीच सीधा अंतःसंयोजन।
- (xxiii) “टर्मिनेटिंग नेटवर्क” से वह नेटवर्क अभिप्रेत है जिससे दूरसंचार संदेश का रिसीवर सीधे जोड़ दिया जाता है।
- (xxiv) “ट्रांजिट नेटवर्क” से वह नेटवर्क अभिप्रेत है जिसके जरिए प्रारंभिक नेटवर्कों अथवा अन्य ट्रांजिट नेटवर्कों से दूरसंचार संदेश भेजे जाते हैं और प्रारंभिक अथवा अन्य ट्रांजिट नेटवर्कों को पहुंचा दिए जाते हैं।
- (xxv) “उपभोग प्रभार” से वह प्रभार अभिप्रेत है जो किसी सेवा प्रदाता द्वारा अपने नेटवर्क से दूरसंचार संदेश भेजने/प्रदान करने/एकत्र करने के लिए दिया जाता है।

- (xxvi) इस नियम में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इसमें परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उस अधिनियम में है।
- (xxvii) “डबल्यूएलएल (एम) ” से एक थोड़ी दूरी के प्रभार क्षेत्र के भीतर स्थानीय लूप प्रौद्योगिकी में बेतार के प्रयोग द्वारा सीमित टेलीफोनी सेवा अभिप्रेत है।

खंड III

3. अंतःसंयोजन प्रभार (इंटरकनेक्शन चार्जेज) :

- (i) इस विनियम में जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लिखित न हो, अंतःसंयोजन प्रभार लागत पर आधारित होंगे।
- (ii) लागत आधारित अंतःसंयोजन प्रभारों के निर्धारण के लिए मुख्य आधार “संवृद्धक अथवा अतिरिक्त” लागत होगा जो अंतःसंयोजन प्रदाता द्वारा अंतःसंयोजन की व्यवस्था करने के लिए सीधे प्रदान किया जाना है।
- (iii) कोई भी सेवा प्रदाता अंतःसंयोजन के प्रभार वसूल करने में सेवा प्रदाताओं के बीच भेदभाव नहीं करेगा।

किन्तु शर्त यह है कि विशेष अंतःसंयोजन सुविधा प्रदान करने के लिए उठाई गई लागत में पर्याप्त अंतर का औचित्य सिद्ध होने पर भिन्न प्रभार वसूल किया जाए।

- (iv) किसी सेवा प्रदाता से ऐसी किसी अंतःसंयोजन सुविधा के लिए प्रभार नहीं वसूला जाएगा जिसने ऐसी सुविधा न मांगी हो अथवा जिसे उसकी आवश्यकता न हो।

किन्तु शर्त यह है कि यदि अंतःसंयोजन सुविधा उसके प्राप्तकर्ता द्वारा मांगने अथवा अपेक्षित होने के रूप में प्रदान नहीं की जा सकती है, तो इस मसले पर अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता और प्रदाता के बीच आपसी सहमति पर निर्णय ले लिया जाए। यदि ऐसी सहमति संभव न हो, तो निर्णय के लिए मामले को प्राधिकरण को भेज दिया जाए। अंतःसंयोजन प्रदाता, अंतःसंयोजन सुविधा प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता को इस बात की सूचना देगा कि अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता द्वारा मांगी गई अथवा अपेक्षित सुविधा प्रदान की जा सकती है या नहीं।

- (v) अंतःसंयोजन प्रदान करने के लिए प्रयुक्त नेटवर्क में घटकों के प्रभारों को लेकर अंतःसंयोजन प्रदाता (प्रदाताओं) और अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता (प्राप्तकर्ताओं) के बीच कोई पारस्परिक समझौता न होने की स्थिति में अंतःसंयोजन प्रदान करने के लिए प्रयुक्त नेटवर्क के घटकों के प्रभार प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर बताए अनुसार होंगे। यदि किसी मामले में प्रार्थित अंतःसंयोजन तथा/अथवा तत्सम्बन्धी प्रभार को लेकर इस आशय के अनुरोध की तारीख के 30 दिन के भीतर कोई पारस्परिक समझौता नहीं हो पाता तो मामले के निर्धारण के निमित्त दोनों पक्षकार अपनी नेटवर्क घटक लागतों और ट्रैफिक के ब्यौरों सहित टीआरएआई से संपर्क करेंगे। मामले के इस प्रकार निर्धारण होने तक यदि उनके बीच कोई मौजूदा व्यवस्था है तो वह जारी रहेगी।
- (V)(क) अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ताओं और अंतःसंयोजन प्रदाताओं के बीच मौजूदा व्यवस्थाएं, यदि कोई हों तो तब तक वैध रहेंगी जब तक कि प्राधिकरण की सहमति से अथवा किसी विनियामक संकल्प के आधार पर उन्हें बदल नहीं दिया जाता।
- (vi) जब तक विशेष रूप से व्यवस्था न की गई हो, प्राधिकरण अंतःसंयोजन से संबंधित मामले से अलग है।

- (vii) जहां प्राधिकरण कुछ समय के लिए अंतःसंयोजन प्रभार निर्दिष्ट करने से स्वयं को अलग रखे, तो ऐसे प्रभारों पर अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता और प्रदाता आपसी सहमति से निर्णय लेंगे।
- (viii) अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता और प्रदाता के बीच अंतःसंयोजन प्रभारों के बारे में आपसी सहमति इस खंड में प्रतिपादित सिद्धांतों पर आधारित होगी।
- (ix) जहां प्राधिकरण के हस्तक्षेप न करने वाले प्रभारों की प्रक्रिया शुरू करने के तीन महीने के भीतर अंतःसंयोजन प्रभार पर आपसी सहमति न हो पाए, तो प्राधिकरण मामले का निपटान करने के लिए अपनी ओर से अथवा किसी भी पक्ष के आवेदन करने पर हस्तक्षेप कर सकता है।

खंड IV

4. राजस्व भागीदारी व्यवस्था :

- (i) अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता और अंतःसंयोजन प्रदाता के बीच सेवा प्राप्त करने, जिसमें अंतःसंयोजन प्रदाता के नेटवर्क का उपयोग करना शामिल है, के लिए उपभोक्ता द्वारा अदा की जाने वाली धनराशि में से राजस्व का बंटवारा किया जाएगा।
- (ii) जब तक कि इस नियम की अनुसूचियों में विशेष रूप से व्यवस्था न की गई हो, प्राधिकरण राजस्व भागीदारी व्यवस्था के मामले में स्वयं को दूर रखेगा।

- (iii) जहां प्राधिकरण, फिलहाल, किसी दूरसंचार सेवा अथवा उसके किसी भाग के लिए राजस्व भागीदारी व्यवस्था निर्दिष्ट करने से स्वयं को दूर रखेगा, ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में सेवा प्रदाता आपसी सहमति से निर्णय लेंगे।
- (iv) जहां राजस्व भागीदारी के सम्बन्ध में जिसके बारे में प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था, राजस्व भागीदारी की ऐसी प्रक्रिया शुरू करने के तीस दिनों के भीतर अंतःसंयोजन प्रभार पर पारस्परिक समझौता न हो पाए, वहां प्राधिकरण मामला निपटाने के लिए अपनी ओर से अथवा किसी भी एक पक्ष के आवेदन करने पर हस्तक्षेप कर सकता है।
- (v) राजस्व भागीदारी के सम्बन्ध में अन्तःसंयोजन प्रदाता (प्रदाताओं) और प्राप्तकर्ता (प्राप्तकर्ताओं) के बीच किसी पारस्परिक समझौते के न होने की स्थिति में राजस्व भागीदारी, विनियम की सूचियों में बताए अनुसार होगी। यदि किसी मामले में अंतःसंयोजन की सुविधाओं के लिए अनुरोध की तारीख के 30 दिन के भीतर कोई पारस्परिक समझौता नहीं हो पाता तो मामले के निर्धारण के निमित्त दोनों पक्षकार अपनी नेटवर्क घटक लागतों और ट्रैफिक के ब्यौरों सहित टीआरएआई से संपर्क करेंगे। मामले की इस प्रकार निर्धारण होने तक यदि उनके बीच कोई मौजूदा व्यवस्था है तो वह जारी रहेगी।
- (V)(क) अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ताओं और अंतःसंयोजन प्रदाताओं के बीच मौजूदा व्यवस्थाएं, यदि कोई हों तो तब तक वेध रहेंगी जब तक कि पाधिकरण की सहमति से अथवा किसी विनियामक संकलन के आधार एवं इनके उद्देश्य नहीं दिया जाता।

खंड V

5. रिपोर्ट करने संबंधी शर्त :

- (i) सभी सेवा प्रदाता इस नियम के अधीन पहली बार निर्दिष्ट अंतःसंयोजन प्रभार और राजस्व भागीदारी व्यवस्थाओं तथा तत्पश्चात हुए परिवर्तनों के संबंध में रिपोर्ट करने की शर्त का अनुपालन करेंगे। इसमें वह अंतःसंयोजन प्रभार और राजस्व भागीदारी की व्यवस्थाएं शामिल हैं जिन पर सेवा प्रदाताओं में पारस्परिक आधार पर निर्णय किया जाएगा।

- (ii) सेवा प्रदाता 45 कार्य दिवसों की अनिवार्य सूचना अवधि के बाद, प्रस्तावित अंतःसंयोजन प्रभारों एवं राजस्व भागीदारी व्यवस्थाओं को लागू कर सकता है बशर्ते कि प्राधिकरण ने इस अवधि के भीतर अन्यथा सीधे निर्देशन न दिया हो।

सिवाय इसके कि इस नियम के लागू हो जाने के पश्चात पहली बार प्राधिकरण को रिपोर्ट दिए जाने के लिए अंतःसंयोजन प्रभार एवं राजस्व भागीदारी व्यवस्थाओं के लिए 45 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है।

- (iii) जब कोई अंतःसंयोजन प्रदाता अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता को यह सूचित करता है कि वह उसके द्वारा मांगी गई अंतःसंयोजन सुविधा प्रदान नहीं कर सकता है, तो अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता इस प्रकार की सूचना मिलने के 45 दिनों के भीतर, प्राधिकरण से हस्तक्षेप का अनुरोध कर सकता है।

- (iv) कोई भी सेवा प्रदाता रिपोर्ट करने संबंधी शर्त का अनुपालन किए बिना अंतःसंयोजन प्रभार अथवा राजस्व भागीदारी व्यवस्था अथवा उसके किसी भाग में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

खंड VI

6. समीक्षा :

- (i) प्राधिकरण, समय—समय पर अंतःसंयोजन प्रभार और/अथवा राजस्व भागीदारी व्यवस्थाओं की समीक्षा और उनमें संशोधन कर सकता है।
- (ii) प्राधिकरण, किसी समय भी, किसी प्रभावित पार्टी से संदर्भ प्राप्त होने अथवा पर्याप्त कारणों से किसी अंतःसंयोजन प्रभार अथवा राजस्व भागीदारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के साथ—साथ उसमें संशोधन कर सकता है।

खंड VII

7. व्याख्यात्मक ज्ञापन :

इस विनियम में स्पष्टता और पारदर्शिता प्रदान करने संबंधी मामलों पर, अनुलग्नक 'क' के रूप में, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन शामिल है।

खंड VIII

8. व्याख्या :

इस विनियम के किसी प्रावधान की व्याख्या के बारे में विवाद उत्पन्न होने पर, प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अनुसूची I

अंतःसंयोजन प्रभार और राजस्व भागीदारी

माद	बुनियादी सेवाओं के लिए राजस्व भागीदारी
1	2
1. लागू करने की तारीख	31 जनवरी, 2002 तक
2. कवरेज	बुनियादी सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क से की जाने वाली कॉलें तथा दूसरे बुनियादी सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली तथा वहीं समाप्त हो जाने वाली कॉलें।
3. स्थानीय कॉलें	प्रत्येक सेवा प्रदाता के लिए बिल बनाना और रखना।
4. घरेलू लम्बी दूरी की कॉलें (एस टी डी कॉलें)	अपने नेटवर्क से कॉल शुरू/प्रेषित करने वाले सेवा प्रदाता को कॉल प्रेषित/समाप्त करने वाले सेवा प्रदाताओं को, परियात के लिए अंतःसम्पर्क से लेकर कॉल समाप्त होने तक के अंतःसंयोजन के समय पर मापी गई कॉल यूनिटों के लिए 0.48 प्रति यूनिट का भुगतान एस टी डी पल्स दर आधार पर करना होगा।
4.(क) सीमित गतिशीलता सहित स्थानीय लूप में बेतार में घरेलू लम्बी दूरी की कॉलें (एस टी डी कॉलें) [डबल्यू एल एल (एम)]	शुरू करने वाले सेवा प्रदाता को अपने नेटवर्क से अंतःसंयोजन बिन्दु से लेकर गन्तव्य स्थल तक और आगे परियात के निमित्त मार्गस्थ सेवा प्रदाता के नेटवर्क तक प्रदत्त ट्रैफिक के सम्बन्ध में अंतःसंयोजन बिन्दु पर मापित कॉल यूनिटों के लिए रु 1.14 प्रति यूनिट का भुगतान एस टी डी पल्स दर आधार पर करना होगा।
	/-
	बशर्ते कि उपर्युक्त 4 अथवा 4(क) में ऐसे किसी प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा जहां अंतःसंयोजन का

	<p>बिन्दु कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (SDCA) हो तथा यह कि ऐसा कोई प्रभास-भुगतान नहीं किया जाएगा जहां टर्मिनेटिंग सेवा प्रदाता ने यह अनुरोध किया हो कि शुरू/प्रेषित करने वाले सेवा प्रदाता द्वारा कॉल गन्तव्य एसडीसीए के बदले एसडीसीए में सौंप दी जाएँ।</p>
5. बुनियादी सेवा में अन्तर्राष्ट्रीय कॉलें	<p>कॉल शुरू करने वाला सेवा प्रदाता, मार्गस्थ सेवा प्रदाता को अंतःसंयोजन के बिन्दु पर मापी जाने वाली कॉल यूनिटों के लिए 0.66 प्रति यूनिट मापित कॉल का भुगतान करेगा।</p> <p>शुरू करने वाले सेवा प्रदाता को मार्गस्थ सेवा प्रदाता को अंतःसंयोजन के बिन्दु पर मापी जाने वाली कॉल यूनिटों के लिए रु.1.14 प्रति यूनिट मापित कॉल का भुगतान करना होगा।</p>
5(क) सीमित गतिशीलता सहित स्थानीय लूप में बेतार में अंतर्राष्ट्रीय कॉलें डबल्यू एल एल (एम)	<p>टिप्पणियां:</p> <p>(क) स्थानीय कॉलेंडु वे कॉलें कहलाती हैं जो एसडीसीए में सेवा प्रदाता के नेटवर्क/एक्सचेज के उपभोक्ताओं द्वारा की जाती हैं और निम्न स्थानों पर समाप्त होती हैं। (i) एक ही एसडीसीए के भीतर अथवा (ii) निकटस्थ एसडीसीए की टेलीफोन एक्सचेज प्रणाली में बशर्ते ये कॉलें केवल गन्तव्य एसडीसीए में दूसरे सेवा प्रदाता के नेटवर्क में वितरित/सौंपी गई हो।</p> <p>(ख) घरेलू लम्बी दूरी की कॉलों के लिए 0.48 प्रति मीटर की गई कॉल पर भुगतान के लिए कॉलों की यूनिटों की संख्या की गणना, अंतःसंयोजन के प्वाइंट और गेटवे टेक्स, जहां तत्पश्चात् कॉल, परियात/समाप्तन के लिए आगे वितरित की जाती</p>

हैं के बीच की अरीय (रिडियल) दूरी के एसटीडी टैरिफ पल्स पर आधारित होगी।

- (ग) डबल्यू एल एल (एम) में घरेलू लम्बी दूरी की कॉलों के लिए ₹ 1.14 प्रति मीटर की गई कॉल पर भुगतान के लिए कॉलों के यूनिटों की संख्या की गणना अंतःसंयोजन बिन्दु और गेटवे टैक्स जहां बाद में कॉल और आगे परियात/समापन के लिए पहुंचाई जाती है के बीच की अरीय (रेडियल) दूरी के एसटीडी टैरिफ पल्स पर आधारित होगी।
- (घ) पहले वाले नेटवर्क से की जाने वाली कॉलों के लिए बुनियादी सेवा प्रदाता और सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता के बीच राजस्व बंटवारा नहीं किया जाएगा।

अनुसूची - IIअंतःसंयोजन प्रभार और राजस्व भागीदारी

मद	सेल्यूलर मोबाइल के लिए राजस्व भागीदारी
1	2
(1) लागू करने की तारीख	31 जनवरी, 2002 तक
(2) कवरेज	सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से की जाने वाली कॉलें तथा दूसरे बुनियादी सेवा प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से प्रेषित अथवा वहीं समाप्त होने वाली कॉलें।
(3) सेल्यूलर मोबाइल से बुनियादी सेवा उपभोक्ता को की जाने वाली स्थानीय कॉलें	बुनियादी सेवा प्रदाता को, पल्स दर पर मापी गई मीटरित कॉलों के अनुसार रु 1.14 प्रति मीटरित कॉल की दर पर किया जाने वाला भुगतान बुनियादी सेवा स्थानीय कॉल में लागू होग
(4) सेल्यूलर मोबाइल से बुनियादी सेवा उपभोक्ता को की जाने वाली घरेलू लम्बी दूरी की कॉलें	बुनियादी सेवा प्रदाता को भुगतान घरेलू लम्बी दूरी कॉलों में लागू दरों के आधार पर किया जाएगा। अंतःसंयोजन से गन्तव्य स्थान तक समान एसटीडी के लिए बुनियादी सेवा प्रदाता द्वारा करवाई जाने वाली कॉल की दूरी के समान वसूलने योग्य दूरी सहित बुनियादी सेवा लम्बी दूरी की कॉलों में लागू पल्स दर पर मापी गई मीटरित कॉलों की संख्या के अनुसार रु 1.14 प्रति मीटरित कॉल पर प्रभार वसूल किया जाएगा।
(5) सेल्यूलर मोबाइल से अंतर्राष्ट्रीय कॉलें	अंतर्राष्ट्रीय कॉलों में लागू दर पर बुनियादी सेवा प्रदाता को भुगतान/बुनियादी सेवा उपभोक्ता द्वारा की गई समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉल में लागू पल्स दर पर अंतःसंयोजन के प्लाइंट पर मापी गई मीटरित कॉलों की संख्या सहित 1.14 रुपए प्रति मीटरित कॉल पर प्रभार वसूल किया जाएगा।

<p>(6) सेल्यूलर मोबाइल से सेल्यूलर मोबाइल तक कॉलें</p>	<p>बुनियादी सेवा प्रदाता द्वारा अग्रेषित (आंशिक) स्थानीय/घरेलू लम्बी दूरी कॉलों के लिए बुनियादी सेवा प्रदाता को स्थानीय/घरेलू लम्बी दूरी कॉल में लागू दर पर भुगतान किया जाना होगा। उक्त मद 3/मद 4, अर्थात् स्थानीय/लम्बी दूरी कॉलों के लिए बुनियादी सेवा में लागू पल्स दर तथा अंतःसंपर्क से गन्तव्य स्थान तक समकक्ष एसटीडी कॉल के लिए बुनियादी सेवा प्रदाता द्वारा अग्रेषित कॉल की दूरी के समान वसूलने योग्य दूरी की लम्बी दूरी की कॉलों के लिए 1.14 रुपए प्रति मीटरित कॉल, में विनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर राशि की गणना की जाएगी:</p>
<p>टिप्पणियां</p>	<p>(क) बुनियादी सेवा प्रदाताओं द्वारा अग्रेषित कॉलों के लिए राजस्व भागीदारी याने हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कॉलों की परिभाषा वही है जो अनुसूची 1 में टिप्पणी (क) में दी गई है।</p> <p>(ख) सेल्यूलर मोबाइल से बुनियादी सेवा उपभोक्ता तक घरेलू लम्बी दूरी की कॉलों के लिए बुनियादी सेवा प्रदाता को देय राजस्व की राशि का निर्धारण करने के लिए मापी गई कॉलों की यूनिटों की संख्या की गणना बुनियादी सेवा प्रदाताओं के गेटवे टैक्स पर गन्तव्य स्थान कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए)(SDCA) तक मीटरीत ऐसी कॉलों की संख्या के रूप में की जाएगी।</p> <p>(ग) बुनियादी सेवा प्रदाता द्वारा अग्रेषित सेल्यूलर मोबाइल से सेल्यूलर मोबाइल तक घरेलू लम्बी दूरी की कॉलों के लिए 1.14 रुपए प्रति मीटरित कॉल पर बुनियादी सेवा प्रदाता को दी जाने वाले कॉल यूनिटों की संख्या की गणना, अंतःसंरोजन</p>

	<p>के प्लाइंट पर गेटवे टैक्स, जहां आगे कैरिज के लिए कॉल स्वीकृत की जाती है तथा सेवा प्रदाता को गेटवे टैक्स, जिसके नेटवर्क में तत्पश्चात् कॉल सौंप दी जाती है दोनों के बीच अरीय (रेडियल) दूरी के आधार पर की जाती है।</p> <p>(घ) सेल्यूलर मोबाइल से की जाने वाली कॉलों के लिए एक और दूसरे बुनियादी सेवा प्रदाता के बीच राजस्व बंटवारे की व्यवस्था का उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है।</p> <p>(ङ) इस विनियम में किसी सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता के उपभोक्ताओं की ओर से दूसरे सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता के उपभोक्ताओं को की जाने वाली कॉलों के लिए सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं के बीच किसी राजस्व हिस्सेदारी की व्यवस्था के प्रति विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया है।</p>
--	---

अनुबन्ध 'क'

ब्याख्यातक ज्ञापन

- इस विनियम की अनुसूची I में डबल्यूएलएल (मोबाइल) सहित बुनियादी सेवा प्रदाता के नेटवर्क हाथ में रखे टर्मिनलों से शुरू होने वाली तथा पहले से कार्यरत बीएसएनएल/ एमटीएनएल सहित दूसरे बुनियादी सेवा प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से भेजी जाने वाली अथवा वहीं समाप्त होने वाली कालों के संबंध में राजस्व भागीदारी व्यवस्थाएं निर्दिष्ट की गई हैं।
- अनुसूची II में सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता के नेटवर्क से शुरू होने वाली तथा अन्य सेवा प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से भेजी जाने वाली अथवा वहीं समाप्त होने वाली कालों के संबंध में राजस्व भागीदारी व्यवस्थाएं निर्दिष्ट की गई हैं। अंतःसंयोजन से संबंधित छ: प्रमुख मुद्रों के बारे में अपने दिनांक 8 जनवरी 2001 के संकल्प में

प्राधिकरण ने यह निर्धारित किया है कि सीएमएसपी द्वारा अंतःसंयोजन के लिए बुनियादी सेवा प्रदाता को जिस राजस्व का भुगतान किया जाता है उसमें से 5 प्रतिशत हिस्सा बिल तैयार करने और संग्रह तथा अधोध्य ऋणों के निमित्त सीएमएसपी द्वारा अपने पास रख लिया जाए। बुनियादी सेवा प्रदाताको ₹0 1.20 की बजाए ₹0 1.14 प्रति मीटरित काल की दर से भुगतान इस व्यवस्था का परिचायक है। बकाया 5 प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ₹0 0.06 प्रति मीटरित काल यूनिट सीएमएसपी द्वारा अपने पास रख लिया जाएगा।

3. डबल्यूएलएल (मोबाइल) से संबंधित अपने टैरिफ आदेश अर्थात् दिनांक 24 मई, 2001 के दूरसंचार टैरिफ आदेश में, प्राधिकरण ने डबल्यूएलएल (मोबाइल) के लिए राजस्व भागीदारी व्यवस्थाओं के बारे में दूर संचार और सूचना प्राद्योगिकी अभिसरण विषयक समूह के मत को नोट किया।
4. दूस संबंध में प्राधिकरण ने उपर्युक्त टैरिफ आदेश में यह देखा था कि डबल्यूएलएल (मोबाइल) आधारित बुनियादी प्रचालकों और बीएसएनएल सहित राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालकों के बीच राजस्व भागीदारी व्यवस्था, विशेष रूप से डबल्यूएलएल (मोबाइल) लाइनों और स्थिर लाइनों से शुरू होने वाली ट्रैफिक धाराओं के बीच भेद रखने और उन पर अलग अलग ^{प्रभार} वसूलने के निमित्त दो प्रचालकों के एक नेटवर्क से लेकर दूसरे नेटवर्क इंटरफेसों पर अंतःसंयोजन प्रभार और बिल तैयार करने के उपर्युक्त तंत्र स्थापित किए जाने के बाद ही कार्यान्वित की जा सकती है। प्राधिकरण ने आगे यह भी देखा है कि ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी क्योंकि एक्सचेंज नंबरिंग योजना एक स्थिर लाइन अथवा डबल्यूएलएल (मोबाइल) लाइन के बीच कोई भेद नहीं रखती थी। प्राधिकरण ने यह निर्दिष्ट किया कि इसलिए सेवा प्रदाता पारस्परिक करार के माध्यम से अपने एक्सचेंजों में और साथ ही अंतःसंयोजन बिंदुओं (पीओआई) पर भी अपेक्षित तकनीकी प्रणलियां स्थापित करें जिसमें कि डबल्यूएलएल

(मोबाइल) लाइनों और पीओटी लाइनों से आने वाले ट्रैफिक को स्पष्टः अलग किया जा सके जिससे कि दो भिन्न ट्रैफिक धाराओं के ट्रैफिक से अर्जित राजस्व की भागीदारी अलग ढंग से की जाए । इस संबंध में यह ध्यातव्य है कि क्योंकि डबल्यूएलएल (मोबाइल) सेवा को बुनियादी सेवाओं का एक अंग समझ लिया गया है । अतः इस विषय पर टीआरएआई की सिफारिशों में यह स्पष्टतः कहा गया है कि डबल्यूएलएल (मोबाइल) के लिए नंबरिंग योजना वैसी ही होगी जैसी कि बुनियादी सेवा स्थिर संयोजनों के लिए है ।

5. प्राधिकरण घटक आधारित कैरिज प्रभारों का निर्धारण करने में प्रवृत्त है । इस प्रयोजन के लिए सेवा प्रदाताओं से संगत लागत आंकड़े मांगे गए हैं ।
6. पत्तन प्रभार तथा पट्टाशुदा लाइन प्रभार निर्धारित करने वाला एक टीनेयम अलग से जारी किया जाएगा ।

डॉ.हर्ष वर्धन सिंह, सचिव एवं प्रधान सलाहकार
[विज्ञापन III/IV/142/2001/असा.]

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th December, 2001

No. 311-4/2001-TRAI(Econ.)—In exercise of the powers conferred upon it under Section 36 read with clauses (ii), (iii) and (iv) of sub-section (b) of Section 11(1) of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act, 2000, to ensure effective interconnection between different service providers and to regulate arrangements amongst service providers of sharing their revenue derived from providing telecommunication services, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Regulation:—

***THE TELECOMMUNICATION INTERCONNECTION (CHARGES AND
REVENUE SHARING) REGULATION, 2001
(5 of 2001)***

Section I

Title, Extent and Commencement

1. Short title, extent and commencement:
 - (i) This Regulation shall be called “The Telecommunication Interconnection (Charges and Revenue Sharing) Regulation 2001” (The Regulation).
 - (ii) The Regulation shall cover arrangements among service providers for interconnection charges and revenue sharing, for Telecommunication Services, including wireless in local loop with limited mobility [WLL(M)], throughout the territory of India, as also those originating in India and terminating outside India.
 - (iii) The Regulation shall be deemed to have come into force with effect from the date of notification in the official Gazette.

Section II

Definitions

2. In this Regulation, unless the context otherwise requires:
- (i) "Act" means the Telecom Regulatory Authority of India, 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act, 2000.
 - (ii) "Authority" means the Telecom Regulatory Authority of India.
 - (iii) "Basic Telecommunication Services" mean services derived from Public Switched Telephone Network (PSTN).
 - (iv) "Ceiling(s)" mean(s) the upper limit(s) for interconnection charge for telecommunication services as may be specified by the Authority from time to time.
 - (v) "Domestic Long Distance Telecommunication Service" or DLD means the telecommunication services required to connect one local area of a public telecommunication network to another within the territorial limits of India so as to allow for transmission of voice and non-voice signals across different geographical areas.
 - (vi) "Floor" means the lower limit of interconnection charges for a telecommunication service as may be specified by the Authority from time to time below which such charges may not be offered.
 - (vii) "Forbearance" denotes that the Authority has not, for the time being, notified any interconnection charge or revenue sharing arrangement for a particular telecommunication service and the service provider is free to fix any charge for such service.
 - (viii) "Interconnection" means the commercial and technical arrangements under which service providers connect their equipment, networks and services to enable their customers to have access to the customers, services and networks of other service providers.
 - (ix) "Interconnection Charge" means the charge for interconnection by an interconnection provider to an interconnection seeker.
 - (x) "Interconnection Provider" means the service provider to whose network an interconnection is sought for providing telecommunication services.
 - (xi) "Interconnection Seeker" means the service provider who seeks interconnection to the network of the interconnection provider.

- (xii) "International Long Distance Telecommunication Service" means telecommunication services required to connect a local area of a public telecommunication network within India to a local area of a public telecommunication network in another country so as to allow for the transmission of voice and non-voice signals.
- (xiii) "International Subscriber Dialing" (ISD) means direct interconnection between an end user in India with another end user in another country by means of direct dialing through public networks.
- (xiv) "Leased Circuits" means telecommunication facilities leased to subscribers or service providers to provide for technology transparent transmission capacity between network termination points which the user can control as part of the leased circuit provision and which may also include systems allowing flexible use of leased circuit bandwidth.
- (xv) "Non-discrimination in interconnection charge" means that service providers shall not, in the matter of interconnection charges, discriminate between service providers except on the basis of substantial cost-differential, and that too only to the extent justified by such cost differential.
- (xvi) "Order" means the Telecommunication Tariff Order, 1999.
- (xvii) "Originating Network" means the network to which an originator of a telecommunication message is proximately connected to.
- (xviii) "Originating/Transit/Terminating Service Provider" means the service provider whose network is used for originating/transit/terminating a telecommunication message respectively.
- (xix) "Regulation" means The Telecommunication Interconnection (Charges and Revenue Sharing) Regulation 2001.
- (xx) "Reporting Requirement" means the obligation of a service provider to report to the Authority at least 45 working days before implementing any new interconnection charge and revenue sharing arrangement for telecommunication services under this Regulation and any changes thereafter.
- (xxi) "Set Up Costs Of Interconnection" means the initial cost of any engineering work needed to provide the specific interconnection facilities requested.

- (xxii) “Subscriber Trunk Dialing”(STD) means direct interconnection between two end users within India by means of direct dialing through public networks.
- (xxiii) “Terminating Network” means the network to which a receiver of a telecommunication message is proximately connected to.
- (xxiv) “Transit Network” means the network through which telecommunication messages from originating networks or other transit networks are transmitted and delivered to terminating or other transit networks.
- (xxv) “Usage Charge” means the charge levied by a service provider for carriage of telecommunication traffic on its network.
- (xxvi) “WLL(M)” means limited mobility telephony service using wireless in local loop technology within a short distance charging area.
- (xxvii) Words and expressions used in this Regulation and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

Section III

3. Interconnection Charges

- (i) Interconnection charges shall be cost based, unless as may be specified otherwise.
- (ii) For determining cost based interconnection charges, the main basis shall be "incremental or additional" costs directly attributable to the provision of interconnection by the interconnection provider.
- (iii) No service provider shall discriminate between service providers in the matter of levying of charges for interconnection.

Provided that a different charge may be levied if justified on the basis of a substantial difference in costs incurred for providing that particular interconnection.

- (iv) No service provider shall be charged for any interconnection facility it does not seek or require.

Provided that if interconnection facility cannot be provided in the form that is sought or required by the interconnection seeker, the issue may be decided mutually between the seeker and provider of interconnection. In case such mutual agreement is not possible, the matter may be reported to the Authority for a decision. The interconnection provider shall inform the interconnection seeker within 30 days of the request for interconnection facilities whether the facilities can be provided in the form sought or required by the interconnection seeker.

- (v) In the absence of a mutual agreement between the Interconnection provider(s) and the seeker(s), in respect of charges for the elements of the network used to provide interconnection, charges for the elements of the network used to provide Interconnection will be as specified by the Authority from time to time. In the event mutual agreement is not arrived at in respect of the interconnection sought and / or charges therefor, within 30 days from the date of such request , both the parties will approach TRAI with the details of their network element costs and traffic particulars for a determination in the matter. Pending such a determination the existing arrangement, if any, will continue.
- (v)(a) The existing charging arrangements, if any, between the Interconnection seekers and Interconnection providers shall hold good until changed with the concurrence of the Authority, or on the basis of a regulatory determination.
- (vi) Unless specifically so provided, the Authority has forbore with respect to interconnection charges.
- (vii) Where the Authority has, for the time being, forbore from specifying interconnection charges, interconnection seekers and providers shall mutually decide on such charges.
- (viii) Interconnection charges mutually agreed among interconnection seeker and provider shall be based on the principles enunciated in this Section.
- (ix) Where mutual agreement for interconnection charges cannot be reached within 30 days of initiating such a process for charges with respect to which the Authority has forbore, the Authority may intervene to settle the matter *suo motu* or on the application of either party.

Section IV

4. Revenue Sharing Arrangements

- (i) Any revenue sharing among interconnection seeker and interconnection provider shall take place out of the proceeds of the amount payable by the subscriber for obtaining the service which involves the usage of the network of the interconnection provider.
- (ii) Unless specifically provided in the Schedules to this Regulation, the Authority forebears with respect to revenue sharing arrangements.
- (iii) Where the Authority has, for the time being, forbore from specifying revenue sharing arrangements for any telecommunication service or part thereof, service providers shall mutually decide on such arrangements.
- (iv) Where mutual agreement for revenue sharing cannot be reached within 30 days of initiating such a process for revenue sharing with respect to which the Authority has forbore, the Authority may intervene to settle the matter *suo motu* or on the application of either party.
- (v) In the absence of a mutual agreement between the Interconnection provider(s) and the seeker(s), in respect of revenue sharing, the revenue sharing will be as specified in the Schedules to this Regulation. In the event mutual agreement is not arrived at in respect of the interconnection sought and / or revenue sharing therefore, within 30 days from the date of such request, both the parties will approach TRAI with the details of their network element costs and traffic particulars for a determination in the matter. Pending such a determination, the existing arrangement, if any, will continue.
- (v)(a) The existing arrangements, if any, between the Interconnection seekers and Interconnection providers shall hold good until changed with the concurrence of the Authority, or by a regulatory determination.

Section V

5. Reporting Requirement

- (i) All service providers shall comply with the Reporting Requirement in respect of interconnection charges and revenue sharing arrangements specified for the first time under this Regulation, as also all subsequent changes. This includes interconnection charges and revenue sharing arrangements that are decided on a mutual basis among service providers.

- (i) The service provider may implement the proposed interconnection charges and revenue sharing arrangements after the mandatory notice period of 42 working days, unless the Authority within such period directs otherwise.

Except that an additional period of 45 days is provided for interconnection charges and revenue sharing arrangements to be reported to the Authority for the first time after the implementation of this Regulation.

- (ii) When an interconnection provider informs the interconnection seeker that it cannot provide interconnection as sought for by the latter, the interconnection seeker, within 45 days of being so informed, may approach the Authority for seeking its intervention.
- (iv) No service provider shall alter any interconnection charge or revenue sharing arrangement, or any part thereof, without complying with the Reporting Requirement.

Section VI

6. Review

- (i) The Authority may, from time to time, review and modify an interconnection charge and/or revenue sharing arrangements.
- (ii) The Authority may also at any time, on reference from any affected party, and for good and sufficient reasons, review and modify any interconnection charge or revenue sharing arrangements.

Section VII

Explanatory Memorandum

This Regulation contains at Annex A, an explanatory memorandum to provide clarity and transparency to matters covered under this Regulation.

Section VIII

8. Interpretation

In case of dispute regarding interpretation of any of the provisions of this Regulation, the decision of the Authority shall be final and binding.

SCHEDULE I
INTERCONNECTION CHARGE AND REVENUE SHARING

ITEM	REVENUE SHARING FOR BASIC SERVICES
<u>(1) Date of Implementation</u>	BY 31ST JANUARY, 2002
<u>(2) Coverage</u>	Calls originating in a basic service provider's network and transmitted through or terminated in another basic service provider's network.
<u>(3) Local calls</u>	Bill and keep for each service provider.
<u>(4) Domestic long distance calls (STD calls) in Basic Service</u>	The originating/transit service provider to pay Rs. 0.48 per unit of measured call for traffic delivered from its network to the network of the transit/terminating service provider for the call units measured at the point of interconnection for its further carriage from the point of interconnection to destination, based on the STD pulse rate.
<u>(4.A) Domestic long distance calls (STD calls) in Wire less in Local Loop with limited mobility [WLL(M)]</u>	The originating service provider to pay Rs. 1.14 per unit of measured call for traffic delivered from its network to the network of the transit service provider for the call units measured at the point of interconnection for its further carriage from the point of interconnection to destination, based on the STD pulse rate.
	Provided no such charge either in (4) or (4.A) above shall be payable if the point of interconnection is at the destination Short Distance Charging Area (SDCA) and also provided that no such charge will be payable if the terminating service provider requests that the call be handed over by the originating/transit service provider at an SDCA other than the destination SDCA.
<u>(5) International calls in Basic Service</u>	The originating service provider to pay Rs. 0.66 per unit measured call to the transit service provider as may be applicable, for the call units to be measured at the point of interconnection.
<u>(5.A) International calls in Wire Less In Local Loop with limited mobility [WLL(M)]</u>	The originating service provider to pay Rs. 1.14 per unit measured call to the transit service provider as may be applicable, for the call units to be measured at the point of interconnection.

	<p><u>Notes:</u></p> <p>(a) “Local calls” are calls which originate from subscribers of a service provider’s network/exchange system in a SDCA and terminate either (i) within the same SDCA or (ii) in the contiguous telephone exchange system of the adjacent SDCA, provided these are delivered/handed over to another service provider’s network in the destination SDCA only.</p> <p>(b) For domestic long distance calls in Basic Service other than WLL(M), number of units of calls for payment at Rs. 0.48 per metered call to be calculated based on the STD tariff pulse for the radial distance between the point of interconnection and the Gateway TAX where the call is subsequently delivered for further carriage/termination.</p> <p>(c) For domestic long distance calls in WLL (M), number of units of calls for payment at Rs. 1.14 per metered call to be calculated based on the STD tariff pulse for the radial distance between the point of interconnection and the Gateway TAX where the call is subsequently delivered for further carriage/termination.</p> <p>(d) No revenue is to be shared between basic service provider and cellular mobile service provider for calls originating from the former network.</p>

SCHEDULE II
INTERCONNECTION CHARGE AND REVENUE SHARING

ITEM	REVENUE SHARING FOR CELLULAR MOBILE
(1) Date of Implementation	BY 31 ST JANUARY, 2002
(2) Coverage	Calls originating in a cellular mobile service provider's network and transmitted through or terminated in another service provider's network.
(3) Local calls from cellular mobile to basic service subscriber	Payment to basic service provider at the rate of Rs. 1.14 per metered call, with number of metered calls measured at the pulse rate applicable to a basic service local call.
(4) Domestic Long distance calls from cellular mobile to basic service subscriber	Payment to basic service provider at a rate applicable to domestic long distance calls. The charge shall be Rs. 1.14 per metered call, with the number of metered calls measured at the pulse rate applicable to basic service long distance calls, with the chargeable distance equal to the distance of the call carried by the basic service provider for an equivalent STD from point of interconnection to destination.
(5) International calls from cellular mobile	Payment to basic service provider at a rate applicable to international calls. The charge shall be Rs. 1.14 per metered call, with the number of metered calls measured at the point of interconnection at a pulse rate applicable to an equivalent international call made by a basic service subscriber.
(6) For calls from cellular mobile to cellular mobile	For local/domestic long distance calls carried (partly) by basic service provider, an amount to be paid to basic service provider at a rate applicable to local/domestic long distance call. The amount to be calculated on the basis of the corresponding conditions specified in Item 3/Item 4 above, i.e. Rs. 1.14 per metered call, pulse rate applicable to basic service local/long distance calls, and for long distance calls the chargeable distance equal to the distance of the call carried by the basic service provider for an equivalent STD call from point of interconnection to destination. Notes: (a) The definition of "local calls" to ascertain revenue sharing with basic service providers for calls carried by them is the same as in note (a) in Schedule I. (b) For domestic long distance calls from cellular mobile to basic service subscriber, number of units of measured calls for determining the amount of revenue payable to basic service provider to be calculated as the number of such calls measured at the basic service provider's Gateway TAX up to the destination Short Distance Charging Area (SDCA). (c) For domestic long distance calls from cellular mobile to cellular mobile carried by basic service provider, number of call units to be paid to the basic service provider at Rs. 1.14 per metered call to be calculated based on the radial distance between the Gateway TAX at the point of interconnection where the call is accepted for further carriage and the Gateway TAX of the service provider to whose network the call is subsequently handed over. (d) For calls originating from cellular mobile, revenue sharing arrangements among one basic service provider and another basic service provider to be as specified in Schedule I.

	(e) This Regulation does not specifically address any revenue sharing arrangement among cellular mobile service providers for calls from subscribers of any cellular mobile service provider to subscribers of another cellular mobile service provider.
--	--

ANNEXE – A**EXPLANATORY MEMORANDUM**

1. Schedule I of this Regulation specifies revenue sharing arrangements for calls originating in a Basic Service Provider's Network including from WLL (Mobile), hand held terminals and transited or terminated in the Network of another Basic Service Provider, including the incumbents BSNL/MTNL.
2. Schedule II of this Regulation specifies revenue sharing arrangements for calls originating in a cellular mobile service provider's (CMSPs) network and transited or terminated in another service provider's network. In its Determination dated the 8th January, 2001, on six major issues relating to interconnection, the Authority has determined that 5% of the pass through revenue paid to the Basic Service Providers by the CMSPs may be retained by the later to cover there cost of billing and collection and bad debts. Payment to the Basic Service Provider @Rs.1.14 per metered call unit against Rs.1.20 represents this arrangement. The balance 5%, i.e. Rs.0.06 per metered call unit, will be retained by the CMSPs.
3. In its Tariff Order pertaining to WLL(M), i.e. the 14th Amendment to The Telecommunication Tariff Order, 1999 dated 24th May, 2001, the Authority took note of the recommendations of the Group on Telecom and Information Technology Convergence on revenue sharing arrangements for WLL (M).
4. In this context the Authority had noted in the above Tariff Order that revenue sharing arrangement between WLL(M) based basic operators and National Long Distance Operators including BSNL can be implemented only after suitable interconnect charging and billing mechanisms have been installed at the Network to Network Interfaces of the two operators, particularly to distinguish between the traffic streams originating from WLL(M) lines and those from fixed lines, and to charge them differently. The Authority further noted that no such arrangement existed, as the exchange numbering scheme did not distinguish between a fixed line or a WLL(M) line. The Authority had specified that service providers should, therefore, by mutual agreement put in place the required technical systems in their exchanges as well as at the Points of Interconnection (POIs) so as to distinguish clearly the traffic flows originating from WLL (M) lines and POTs lines, so that revenues are shared differently for the two traffic streams. It may be recalled in this connection that since WLL (M) service has been considered as a part of the basic services, it has been clearly mentioned in the TRAI's recommendations on the subject that the numbering plan for WLL (M) will be the same as that of the basic services fixed connections.

5. The Authority is in the process of determining element based carriage charges. The relevant cost data have been sought from service providers for this purpose.

6. A Regulation specifying Port Charges and Leased Line Charges will be issued separately.

DR. HARSHA VARDHANA SINGH, Secy.-cum-Principal Advisor
[ADVT III/IV/142/2001/Exty.]

